भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 120
जिसका उत्तर गुरुवार, 2 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विभिन्न अधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों/अध्यक्षों के रिक्त पद

120. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक सरकार द्वारा स्थापित अधिकरणों का ब्यौरा क्या है ;
(ख) सरकार द्वारा स्थापित अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष और कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;
(ग) अधिकरणों में पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं ; और
(घ) स्थापित किए गए विभिन्न अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों/अध्यक्षों सहित संस्वीकृत पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : सरकार द्वारा स्थापित किए गए प्राधिकरण निम्नानुसार है:-

i. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरण;
ii. आय-कर अपील प्राधिकरण;
iii. सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील प्राधिकरण;
iv. तस्कर विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन अपील प्राधिकरण;
v. केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण;
vi. रेल दावा प्राधिकरण;
vii. प्रतिभूति अपील प्राधिकरण;
viii. ऋण वसूली प्राधिकरण;
ix. ऋण वसूली अपील प्राधिकरण;
x. दूरसंचार विवाद निपटान और अपील प्राधिकरण;
xi. राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण;
xii. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण;
xiii. राष्ट्रीय उपभोगता विवाद निवारण आयोग;
xiv. विद्युत अपील प्राधिकरण;
xv. सशस्त्र बल प्राधिकरण; और
xvi. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ।

(ख) : प्राधिकरणों के अध्यक्ष/प्रधान और अन्य न्यायनिर्णयन सदस्यों के पदों के लिए स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियां **उपाबंध** पर हैं।

(ग) : अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/सदस्य/अन्य सचिवीय कर्मचारिवृन्द की रिक्तियों को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है और ये संबंधित कानूनी उपबंधों के अनुसार समय-समय पर भरी जा रही हैं । प्राधिकरण में पदों के सभी स्तरों पर रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, पदत्याग, पदोन्नति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि के कारण हो रही हैं । प्राधिकरणों में अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/सदस्यों के पदों का न भरा जाना कुछ प्रशासनिक कारणों से है और प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा की शर्तों को शासित करने वाले नियमों के संबंध में विभिन्न न्यायिक मंचों में लंबित मुकदमेबाजी/न्यायिक मामलों के कारणों से भी है ।

(घ) : प्राधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 अधिनियमिति और प्राधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 की अधिसूचना और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप विभिन्न प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में अनुसंधान-सह-चयन समिति (एससीएससी) के गठन से प्रारंभ की गई है । सभी प्राधिकरणों में इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और कुछ मामलों में यह पहले ही एससीएससी द्वारा पुरी कर ली गई है और सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए सिफारिशे प्रस्तुत की गई है ।

****

उपाबंध

राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 120 जिसका उत्तर 2 फरवरी, 2023 को दिया जाना है, में यथा निर्दिष्ट उपाबंध

क्रम सं.	प्राधिकरण का नाम	पद	स्वीकृत पद संख्या	वर्तमान रिक्तियों की स्थिति
1	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरण	पीठासीन अधिकारी	20	9
2	आयकर अपील प्राधिकरण (आईटीएटी)	न्यायिक सदस्य	63	18
		लेखाकार सदस्य	63	25
3	सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील प्राधिकरण (सीईएसटीएटी)	अध्यक्ष	1	0
		सदस्य (न्यायिक)	16	7
		सदस्य (तकनीकी)	16	12
4	तस्कर विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन अपील प्राधिकरण (एसएएफईएमए)	अध्यक्ष	1	0
		सदस्य	4	0
5	केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (सीएटी)	अध्यक्ष	1	0
		न्यायिक सदस्य	34	9
		प्रशासनिक सदस्य	35	12
6	रेल दावा प्राधिकरण (आरसीटी)	अध्यक्ष	1	0
		उपाध्यक्ष (न्यायिक)	2	2
		उपाध्यक्ष (तकनीकी)	2	2
		न्यायिक सदस्य	20	16
		तकनीकी सदस्य	21	8
7	प्रतिभूति अपील प्राधिकरण (एसएटी) (सीएटी)	पीठासीन अधिकारी	1	0
		न्यायिक सदस्य	1	0
		तकनीकी सदस्य	2	1
8	ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी)	पीठासीन अधिकारी	39	4
9	ऋण वसूली अपील प्राधिकरण (डीआरएटी)	अध्यक्ष	5	0
10	दूरसंचार विवाद निपटान और अपील प्राधिकरण	अध्यक्ष	1	0
		सदस्य	2	0
11	राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (एनसीएलटी)	अध्यक्ष	1	0
		न्यायिक सदस्य	31	12
		तकनीकी सदस्य	31	11
12	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण (एनसीएलएटी)	अध्यक्ष	1	0
		न्यायिक सदस्य	5	1
		तकनीकी सदस्य	6	1

13	राष्ट्रीय उपभोगता विवाद निवारण आयोग	अध्यक्ष	1	0
		सदस्य	11	1
14	विद्युत अपील प्राधिकरण	अध्यक्ष	1	1
		न्यायिक सदस्य	1	1
		तकनीकी सदस्य	3	1
15	सशस्त्र बल प्राधिकरण (एएफटी)	न्यायिक सदस्य (जिसमें अध्यक्ष का एक पद शामिल है)	17	7
		प्रशासनिक सदस्य	17	3
16	राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण	अध्यक्ष	1	0
		न्यायिक सदस्य	10	4
		विशेषज्ञ सदस्य	10	5

****